

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय

क्रमांक—प.40(16)मु.म./सहा./2019

जयपुर दिनांक 19.02.2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में गम्भीर घायल होने पर राशि 10,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दुर्घटना के प्रकरणों में गम्भीर घायल होने पर दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर राशि 20,000 रुपये (अक्षरे बीस हजार रुपये मात्र) की गई है।

यह आदेश दिनांक 18.02.2019 से प्रभावी होगा।

(Q)

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समस्त) राजस्थान।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय

क्रमांक—प.40(16)मु.म./सहा./2019

जयपुर दिनांक 19.02.2019

कार्यालय आदेश

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आश्रित को राशि 50,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृत की जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दुर्घटना के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आश्रित को दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर राशि 1,00,000 रुपये (अक्षरे एक लाख रुपये मात्र) की गई है।

यह आदेश दिनांक 18.02.2019 से प्रभावी होगा।



प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यमंत्री सचिवालय।
3. सभागीय आयुक्त, सभाग (समस्त) राजस्थान।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
मुख्य मंत्री सचिवालय
CHIEF MINISTER'S SECRETARIAT

क्रमांक:गुप्त/प.23(2)अ.वा.सा./2001

3820

दिनांक:-

11/11/2001

जिला कलेक्टर (समस्त)

विषय:- जीवन रक्षा कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता की स्वीकृति।

माननीय मुख्यमंत्री जी का प्राथमिकता क्षेत्र होने के कारण "मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष" तथा "मुख्यमंत्री सहायता कोष" से सहायता स्वीकृत करने में काफी प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है तथा रवीकृति भी तत्काल जारी होने लगी है। फिर भी रवीकृति प्रक्रिया के बारे में रामान्य जन और यहाँ तक कि कई शासकीय अधिकारियों को भी पूर्ण जानकारी नहीं होने से प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसलिए पूर्व में जारी आदेशों के कम में निम्न प्रकार रिस्ति स्पष्ट की जाती है:-

1. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष:-

1. इस कोष से केवल उन्हीं व्यक्तियों को इलाज हेतु सहायता स्वीकृत की जाती है जो गरीबी की रेखा से नीचे चयनित परिवार का सदस्य हो। इसके लिए राज्य सरकार ने ऐसे राष्ट्रीय परिवारों को गेड़िकेयर रिलिफ कार्ड उपलब्ध कराये हुए हैं। सभी चिकित्सा, महाविद्यालयों रो संबद्ध चिकित्सालय, जिला अस्पतालों व अन्य सभी राजकीय अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश है कि चिकित्सालय में उपलब्ध दवाईयों पर पहला हक ऐसे परिवारों का है। अतः जब भी बी.पी.एल. परिवार का कोई सदस्य बीमार होकर अस्पताल में आये तो उसे निःशुल्क दवाईयों एवं निःशुल्क संबंधी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसा व्यक्ति आचटडोर जांच की सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। इनडोर दोनों में इलाज कराते हुए निःशुल्क रोवार्ए एवं दवाईयों प्राप्त करने का या इनडोर दोनों में इलाज कराते हुए निःशुल्क रोवार्ए एवं दवाईयों प्राप्त हुई है। अतः जिला कलेक्टर अधिकारी होगा। इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः जिला कलेक्टर अपने जिले के सभी चिकित्सालयों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. कुछ चिन्हित गंभीर बीमारियों, जिनमें इलाज पर काफी रुपया व्यय होता है, के इलाज हेतु बी.पी.एल. परिवार के सदस्यों को शात % सहायता मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से उपलब्ध कराई जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु प्रक्रिया को भी काफी सरल किया गया है तथा स्वीकृति भी तत्काल जारी की जाती है। सहायता स्वीकृत कराने हेतु निम्न कागजात का होना आवश्यक है:-

 1. बीमार व्यक्ति या परिवार के मुखिया का सहायता स्वीकृति हेतु पानीय गुरुख्यमंत्री जी या शारान सचिव, चिकित्सा। वे नाम राया प्रार्थना-पत्र।
 2. इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा प्रदत्त इलाज पर होने वाले व्यय का तख्तीना।
 3. गेड़िकेयर रिलिफ कार्ड की प्रगाणित प्रतिलिपि।

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
मुख्य मंत्री सचिवालय

CHIEF MINISTER'S SECRETARIAT

उपरोक्तानुसार आवेदन—पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय अथवा शारांग राष्ट्रीय चिकित्सा के कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। स्वीकृत सहायता राशि सीधे ही संबंधित चिकित्सालय को भेजी जाती है।

4. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से सहायता तब ही स्वीकृत की जाती है जब इलाज राजकीय चिकित्सालय में कराया जावें। यदि राजस्थान प्रदेश के किसी चिकित्सालय में वांछित विशेषज्ञ उपलब्ध ना हो तो सावई मानरिंग चिकित्सालय, जयपुर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस को केस रेफर होने पर ही सहायता रक्षीकृत की जा सकती है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष रोगियों विकित्सालयों में इलाज कराने पर सहायता देय नहीं है।

2. मुख्यमंत्री सहायता कोषः—

मुख्यमंत्री सहायता कोष रोगियों द्वारा देता होना दुर्घटना में पायल होने पर उनके आश्रितों को शहीद सैनिकों के परिवारों को, विकलांग सैनिकों को तथा कुछ हत्या के प्रकरणों में सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः—

1. इलाज हेतु सहायता— गरीब व्यक्तियों को राजकीय चिकित्सालयों, विशेषज्ञता वाले अस्पतालों तथा ट्रस्टों द्वारा संचालित बड़े चिकित्सालयों में इलाज कराने हेतु सहायता स्वीकृत की जाती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन नियम जारी रखता है। आवेदन के साथ निम्न कागजात का होना आवश्यक हैः—
1. वीगार या परिवार के मुखिया का सहायता स्वीकृति हेतु आवेदन—पत्र।
2. संबंधित चिकित्सक द्वारा इलाज पर होने वाले व्यय का तारीखीना।
3. निम्न भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त परिवार की वार्षिक आय का प्रगाण—पत्र।

इस कोष से सहायता केवल उन्हीं परिवारों को देय है जिनकी वार्षिक आय 24 हजार रुपये से अधिक न हो। जनप्रतिनिधियों को आय प्रगाण—पत्र देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। सहायता स्वीकृत कर सागार्यतः रांबंधित चिकित्सालय को प्रेषित की जाती है जो तारीखीने की 30 से 40 प्रतिशत तक होती है।

2. दुर्घटना में गृत्यु एवं घायल होने पर सहायता— पूर्व में जिला कलेक्टर को अधिकृत किया हुआ है कि दुर्घटना के प्रकरणों में तात्कालिक सहायता का उपलब्ध कर पुरुषभरण मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त कर ले। दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 10 हजार रुपये की सहायता देय है। अगर परिवार राशि है तो सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है।

दुर्घटना में घायलों को चोट के अनुसार सहायता उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। साधारण घायल को अधिकतम दो हजार रुपये की सहायता तथा गंभीर घायलों को अधिकतम पांच हजार रुपये तक की सहायता रक्षीकृत की जा सकती है। सहायता रक्षीकृत करते साथ जिला कलेक्टर को प्रकरण के बारे में रांतुरि कर लेनी चाहिए।

3. हत्या के प्रकरणों में सहायता— माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30वीं छालही में यह निर्णय लिया है कि हत्या के कुछ प्रकरणों में भी परिवार को आर्थिक सहायता रक्षीकृत की जावे। परन्तु यह सहायता मुख्यमंत्री कार्यालय से ही स्वीकृत होगी,

राजस्थान सरकार
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
मुख्य मंत्री सचिवालय
CHIEF MINISTER'S SECRETARIAT

जिला स्तर से नहीं। इसके लिए सहायता उन्हीं प्रकरणों में रवीकृत वर्गी जा सकेगी जिनमें परिवार की वार्षिक आय 24 हजार रुपये से कम हो तथा जिसकी हत्या हुई है वह परिवार का मुख्या अथवा कमाऊ सदस्य हो। यदि ऐसे प्रकरण हो तो जिला कलेक्टर अपनी अभिशंबा के साथ प्रकरण रवीकृति हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं।

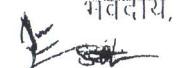
4. शहीद रोगिक परिवारों/विकलांग सैनिकों को सहायता:-

1. दिनांक 1.4.99 के बाद सीमा पर एवं काउन्टर इन्हारजोनी ऑपरेशन में शहीद होने वाले सैनिक एवं आर्मी-सैनिक बलों के सदस्यों के शहीद होने पर उनके आश्रित को तात्कालिक राहायता के रूप में रौनिक कल्याण विभाग से Battle Casualty प्रमाणित होने पर 1.00 लाख रुपये रवीकृति कर जिला कलेक्टर के माध्यम से भिजवाये जाते हैं। यह राशि शहीद की पत्नि को तथा अविवाहित होने की दशा में सैनिक रिकार्ड के अनुसार शहीद के माता/पिता को दी जाती है।
2. यदि शहीद विवाहित हो तो उसके माता-पिता के नाम पोर्ट ऑफिस में संयुक्त खाता खुलवाने हेतु रुपये 1.02 लाख की राशि जिला कलेक्टर के माध्यम से भिजवाई जाती है। शहीद के अविवाहित होने की दशा में यह राशि देय नहीं है।
3. शहीद का आश्रित 25 बीघा कृषि भूमि (इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में) अथवा मध्यम वर्ग का आवारान मण्डल का मकान नहीं लेना चाहे तो उसे मुंग सहायता कोष से चार लाख रुपये की राशि रवीकृत की जा सकती है।
4. कस्त 2 व 3 की राशि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित गिर्धारित प्रपत्रों की प्राप्ति के बाद ही रवीकृत वर्गी जाती है।
5. युद्ध में स्थाई अपेक्षा हुए सैनिकों को सैनिक कल्याण विभाग के प्रमाणीकरण के बाद रुपये 25000 की नकद सहायता रवीकृत की जाती है। 25 बीघा भूमि की एवज में विकलांग सैनिक रु. 4.00 लाख वर्गी नकद राहायता भी मुंग सहायता कोष से प्राप्त कर सकता है।
6. शहीद सैनिकों के आश्रितों/विकलांग सैनिकों को देय अन्य सुविधाओं हेतु शिवेशक, सैनिक कल्याण विभाग से राष्ट्रपक्ष किंवा जा राक्ता है।

5. अन्य सहायता:- उपरोक्त वर्णित मदों के अतिरिक्त किरी भी प्रकार की सहायता जिला कलेक्टर मुख्यमंत्री सहायता कोष से बिना सचिव(प्रथम), मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति प्राप्त किये, रवीकृत नहीं कर सकेंगे।

कृपया राहायता हेतु प्रकरण भिजवारो रागय नियमों एवं प्रक्रियाओं का ध्यान रखें ताके रवीकृति में विलम्ब नहीं हो।

भवदीय,


 (र.म. मेहता)
 राज्यपाल, मुख्यमंत्रीजी

प्रतिलिपि रांगामीय आयुक्त (रागरता) को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

उप सचिव, मुख्यमंत्रीजी

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री कार्यालय

क्रमांक—प.40(16)मु.म./सहा. / 11

जयपुर दिनांक 15.07.2011

कार्यालय आदेश

राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों/घायलों को दुर्घटना के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में सम्बन्धित जिला कलक्टरों के माध्यम से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। दुर्घटना में पीड़ितों को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, अतः यह अनुभव किया गया है कि उक्त एक वर्ष की अवधि अत्यधिक है, तथा इस कारण से ऐसे प्रकरणों में प्रायः अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

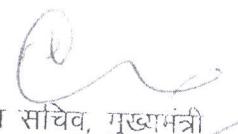
अतः दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों/घायलों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना दिनांक से अधिकतम एक वर्ष के स्थान पर यह अवधि दिनांक 1, अगस्त—2011 से दुर्घटना के दिनांक से अधिकतम 6 माह संशोधित की जाती है।

तदनुसार दुर्घटना के प्रकरणों में 6 माह से पूर्व के प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की जावे।


प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
2. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
3. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समस्त), राजस्थान।
4. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।


प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री सहायता कोष

क्रमांक—प.40(16)मु.स./सहा./12

जयपुर दिनांक 13.12.2012
१५.१२.१२

कार्यालय आदेश

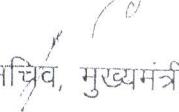
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को राशि ₹20,000 की सहायता दी जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 13.12.2012 से दुर्घटना के प्रकरणों में मृत्यु होने पर आश्रित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि ₹20,000 से बढ़ाकर राशि ₹50,000 (अक्षरे ₹पचास हजार मात्र) की जाती है।


प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:-

1. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समर्त), राजस्थान।
2. जिला कलक्टर (समर्त), राजस्थान।


प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

राजस्थान सरकार
मुख्यमंत्री सहायता कोष

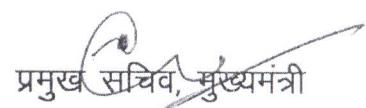
क्रमांक—प.40(16)मु.म./सहा./12

जयपुर दिनांक 02.01.2013

कार्यालय आदेश

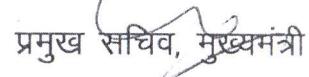
राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में गम्भीर घायल होने पर परिवार को राशि ₹5,000 तक की सहायता दी जाती है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 01.01.2013 से दुर्घटना के प्रकरणों में गम्भीर घायल होने पर दी जाने वाली सहायता राशि ₹5,000 से बढ़ाकर राशि ₹10,000 (अक्षरे दस हजार मात्र) की जाती है।


प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैं:-

1. सम्भागीय आयुक्त, सम्भाग (समस्त), राजस्थान।
2. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।


प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

3/1/13

मुख्य मंत्री कार्यालय
राजस्थान सरकार

क्रमांक—प.40(16)मु.म./सहा./2015
जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान।

जयपुर दिनांक— 28.10.2015

विषय:—मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में शीघ्रता से सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

यह ध्यान में लाया गया है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को 6 माह से अधिक समय उपरांत भी सहायता का भुगतान नहीं किया जाता है। इस मद में मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक जिले में राशि 10-10 लाख रुपये का रिवाल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया हुआ है। दुर्घटना में सहायता के प्रकरणों में समय पर सहायता नहीं देने के कारण तत्काल सहायता दिये जाने का औचित्य समाप्त प्रायः हो जाता है।

दुर्घटना के प्रकरणों में सहायता देने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से अधिकतम अवधि तीन माह में पठवारी/तहसील कार्यालय की रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार देय सहायता राशि सम्बन्धित के खाते में जमा कर दी जावे। मुख्यमंत्री कार्यालय में पुनर्भरण हेतु प्रकरण भिजवाते समय स्वीकृति पत्र में प्रार्थी द्वारा आवेदन करने की दिनांक एवं सहायता राशि को सहायता प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में जमा करने की दिनांक अनिवार्य रूप से अंकित की जावे। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सहायता देने में कितना समय लगाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा केवल सड़क एवं रेल दुर्घटना के प्रकरणों में अन्वेषक अधिकारी की संतुष्टि पर पोस्टमार्टम कराने में शिथिलता प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से केवल सड़क और रेल दुर्घटना के प्रकरणों में अन्वेषक अधिकारी की संतुष्टि पर पोस्टमार्टम नहीं कराने की स्थिति में अन्वेषक अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने हेतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिथिलता प्रदान करने का प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाया जा सकता है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय

सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री